Yarn Sales and Purchase Co-operative Society, Tripura

4377. Shri Dasaratha Deb: Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the accounts of Yarn Sales and Purchase Cooperative Society of Tripura have been audited in 1959-60; and

(b) if so, the main features of the Audit Reports?

The Deputy Minister of Community Development and Cooperation (Shri B S Murthy): (a) The audit of the Yarn Sales and Purchase Society of Tripura for the Cooperative years 1958-59 and 1959-60 is in progress. This society was converted in 1960-61 into an Apex one under the style "The Tripura State Industrial Cooperative Sociey Ltd." Audit of this Apex society for 1960-61 will be taken up after the close of the cooperative year i.e. after 30th June, 1961.

(b) As the audit has not yet been completed—the question does not arise.

Opening of a Railway Hospital at Basti

4378. Shri Ram Shankar Lal: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether between Gorakhpur and Gonda a distance of more than 90 miles on North Eastern Railway there is no Railway Hospital or dispensary and the services of non-railway doctors have to be often called for;

(b) if so, whether it is proposed to open a railway hospital, dispensary or a health centre at Basti midway between Gorakhpur and Gonda; and

(c) when the proposal is likely to be implemented?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) There is no Railway Hospital or dispensary between Gorakhpur and Gonda but there are no reports about non-Railway Doctors being called in for services to be rendered to Railway employees.

(b) and (c). There was a proposal to provide a Health Centre at Basti during 1961-62, but the same has been deferred to 1962-63.

Warehouse for Tea at Calcutta

4379. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned the construction of a multi-storeyed and air-conditioned warehouse for tea at Calcutta;

(b) if so, at what cost; and

(c) what action has been taken in that direction so far?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) Yes.

(b) Rs. 115·65 lakhs.

(c) The foundation work for the Tea Warehouse has been completed. The construction of the superstructure is in progress.

तहसील सहकारी समिति के धन का गबन

४३८०. **श्री पद्म देव :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के जिला महासू की तहसील ठयोग की तहसील सहकारी समिति का लाखों रुपयों का गबन हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस धन के संबंध में कोई जांच नहीं है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां, १,७५,०२१ रु० का गबन इस संस्था में १९५६ तक हुआ।

(ख) इस समय यह कहना कठिन है क्योंकि ऊपर वाली रकम के तीन मुकदमें अदालतों में दायर हैं।

(ग) सहकारी विभाग को संघ के धन की हानि की जब जानकारी हुई तो उन्होंने १९५६ से निम्नलिखित कदम उठाए :—

(१) धन के गबन के लिए जिम्मेवार प्रबन्ध कमेटी से अधिकार ले लिया गया और संघ के कार्यों को सम्हालने के लिए एक प्रशासक मुकर्रर कर दिया गया। जिनसे बड़ा बड़ी रकमें वसूल करनी थीं उनके व उनकी जमानतों और प्रबन्धक समिति के सदस्यों के खिलाफ मालमजमीकदमें तैयार किए गये

(२) प्रशासक ने बाद में रु० ३४०७३·५० की डिगरी ले ली। अब डिगरी की की इजरा दीवानी अदालत में कराई जा रही है।

(३) एक और डिगरी रु० १,५८,०७६.७२ की भी ले ली गई। इसके खिलाफ अपील दायर हुई और मामला अपील वाली अदालत में अभी दायर है।

(४) तीसरा रु० २२,६८६.५१ का मामला मुकदमा मालिक के सामने है।

(५) ऊपर बताए गए दीवानी दावे दायर करने के अलावा नीचे दिए गए फ़ौजदारी दावे भी चलाए गए :

(१) थियोग सहकारी संघ के एजेंट के खिलाफ एक मुकदमा चलाया गया है। उसने संघ के नाम पर एक निजी ट्रक को रास्ते पर चलाने की इजाज़त लेने के जाली मे कागजात बनाए थ। व थियोग में पहले दर्जे के न्यायाधीश के सामने मुलजिम है।

(२) एजेंट के खिलाफ एक और ५०,००० रूपये के मुकदमे की जांच हो रही है। यह रकम १,५८,०७६.७२ की डिगरी में शामिल है।

(६) संघ को ऋण-निस्तार-अधिकारी के अधीन कर दिया गया है और वह इन दावों की पैरवी कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा धन का गबन

४३८१. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० तक हिमाचल प्रदेश में जिलावार सहकारी समितियों और संगठनों का कितना-कितना रुपया गबन हुआ था ; और

(ख) उक्त राशियों की वसूली के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जिलेवार जानकारी नीचे दी गई है :

नाम जिला	अन्तर्ग्रस्त समितियां	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त धन (रुपये)
(१) महासू . . .	२२	७६	४,७५,३७१.१५
(२) बिलासपुर . . .	१	१	३८०.००
(३) चम्बा	१	१	१,०००.००
(४) मण्डी . . .	१४	१४	५३,४०२.३१
योग . . .	३८	९२	५,३०,१५३.४६